सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

कानपुर, शुक्रवार, 21 मार्च, 2025
वर्षः 02, अंकः 84, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड जालसाज पीड़िता के शिकंजे में अधिवक्ता... » Pg03

राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं: मुख्यमंत्री

» Pg12

भड़के वकीलः कहा- सख्त कार्रवाई जरूरी

राज्यसभा में गूंजा जज के घर नकदी का मामला

न्यायिक हलकों में हड़कंपः धनखड़ का सवाल- खुलासे में देरी क्यों? कॉलेजियम ने मूल हाई कोर्ट वापस भेजा

» कार्यालय संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में लगी आग ने न केवल न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया, बल्कि एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने लाया। आग बुझाने के बाद घर से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी ने सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए, इस मामले की गहराई में जाएं और जानें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसके जवाब में क्या कदम उठाया।

इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है। फिर भी, कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। जजों का मानना है कि यदि न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो चीफ जस्टिस को 1999 की प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच का प्रावधान है।

आग लगने पर घर में मौजूद नहीं थे जस्टिस यशवंत वर्मा

बताया जा रहा है कि जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी, उस समय वह शहर में नहीं थे। उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली।

अक्टूबर 2021 में इलाहबाद हाईकोर्ट से हुआ था ट्रांसफर

बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सीजेआई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तत्काल तबादले का निर्णय लिया और उन्हें उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। बता दें कि जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित हुए थे।

इन-हाउस जांच की मांग

कुछ जजों की राय है कि केवल तबादले से न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। यदि वे ऐसा करने से मना करते हैं, तो उनके खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू करनी चाहिए। ऐसा न होने पर जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट सकता है। दरअसल कई जज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1999 में स्थापित इन-हाउस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह प्रक्रिया संवैधानिक न्यायालय के जजों पर भ्रष्टाचार, गलत आचरण या अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए बनाई गई है। इसके तहत, सीजेआई को शिकायत मिलने पर संबंधित जज से जवाब मांगा जाता है।

» बंगले में लगी आग तो घर से निकला कैश का भंडार।

पुलिस को अवैध तरीके से धन रखने का हुआ था शक

इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। इसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। जस्टिस वर्मा के आवासीय बंगले में लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जब आग लगी जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया था। आग बुझाए जाने के बाद कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। यह संदेह हुआ कि यह पैसे अवैध तरीके से रखे गए थे।

सांसद जयराम रमेश ने सभापति का मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए कोई व्यवस्था ढूंढ़ेंगे। सुबह के सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही पर सभापति का जवाब मांगा और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस की याद दिलाई। धनखड़ ने कहा कि उन्हें जो बात परेशान करती है, वह यह है कि घटना के बाद भी वो तुरंत प्रकाश में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती, तो संबंधित व्यक्ति तुरंत हिट लिस्ट पर आ जाता।

लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में मृत पाया गया यात्री

मचा हड़कंप

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री मृत पाया गया। घटना शुक्रवार सुबह 8.10 बजे की है। जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 2845 में यात्री का शव मिला। एयर इंडिया की यह फ्लाइट नई दिल्ली से आई थी। एक साथी यात्री के अनुसार, पीड़ित की पहचान बिहार के गोपालगंज के 52 वर्षीय आशिफ दौला अंसारी के रूप में हुई है। जब एक परिचारिका उसके भोजन की प्लेट और पेय

विमान में मौजूद डॉक्टरों ने की जांच

पदार्थ साफ करने के लिए उसके पास आई, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंसारी के पास बैठे डॉक्टरों के एक ग्रुप ने उसकी जांच की और पुष्टि की कि उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने कहा कि पीड़ित ने अपनी सीटबेल्ट भी नहीं खोली थी और न ही अपने भोजन की प्लेट को छुआ था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह एक पुरुष यात्री लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। जिसकी हालत ठीक नहीं थी। हमारी मेडिकल टीम ने तुरंत जांच की। उसे एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार प्रदान किया। हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस कठिन समय में हम उसके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि, अंसारी की मौत किस वजह से हुई, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने कहा कि वो घटना की जांच कर रहे हैं।

बिहार के गोपालगंज निवासी 52 वर्षीय आशिफ दौल्ला अंसारी नामक यात्री विमान में बेहोश पाया गया। एयर इंडिया की उड़ानविमान संख्या एआई 2845 शुक्रवार को प्रातः 8:10 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। साथी यात्रियों ने देखा कि अंसारी बिना हिले-डुले खड़े थे, उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी और भोजन भी सुरक्षित था, जबकि केबिन क्रू ने उनकी थाली को साफ करने की कोशिश कर रही थी।

विमान में मौजूद चिकित्सा पेशेवरों ने तुरंत उनकी जांच की, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण लक्षण की पुष्टि नहीं हुई, इसके बाद हवाई अड्डे के चिकित्सा कर्मचारियों ने उन्हें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, जहां बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई।

अनोखा मेला,अलौकिक दृश्य..

आज भी कनपुरिए होली की परंपरा को सहेजे हुए हैं

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । गंगा मेला का समापन शाम के समय जिला कारागार के निकट स्थित सरसैय्या घाट पर होता है। देश में शायद ही कोई ऐसा मेला होगा जहां पूरे शहर के लोग गले मिलने आते होंगे, एक दूसरे को बधाइयां देने आते होंगे। कानपुर की यह अनूठी परंपरा कचहरी के निकट स्थित चेतन चौराहे से सरसैया घाट तक एक भव्य दृश्य उपस्थित करती है। जहां सड़क के दोनों ओर जिला प्रशासन, राजनीतिक दलों विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवी वर्ग के शिविर लगे होते हैं। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित सभी विभागों के आला अधिकारी, सांसद, विधायक महापौर, सहित राजनीतिक जगत की सभी प्रमुख हस्तियां हम कह सकते हैं शहर के सभी खास-ओ-आम इस 500 मीटर के रेंज में ही उपस्थित होते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं । बधाई उस समय के कानपुर के पूर्वजों द्वारा अंग्रेजों को पराजित करने की । बधाई अपनी इस परंपरा को सहेजने की बधाई कनपुरिया संस्कृत को जीवित रखने की ।

जहां एक ओर होली पूरे देश में एक दिन खेली जाती है उस होली को कानपुर के लोग सात दिन तक खेलते थे। आज भी कनपुरिए होली की परंपरा को सहेजे हुए हैं ।

बस अंतर इतना आ गया है कि अब होली सात दिन तो नहीं खेली जाती लेकिन होली से अधिक रंगबाजी गंगा मेला के दिन कानपुर में नजर आती है ।

गंगा मेला वाले दिन पूरे कानपुर में जबरदस्त रंगबाजी होती है । इस पूरे महोत्सव के दो केंद्र होते हैं सुबह हटिया का रज्जन बाबू पार्क जहां झंडारोहण के साथ रंग का ठेला निकलता है तो वहीं शाम को सरसैया घाट पर मेला लगता है। हटिया के रज्जन बाबू पार्क से निकला रंग का ठेला जिन-जिन मार्गो से गुजरता है, उन मार्गों पर केवल रंगबाज कनपुरियों का रेला ही नजर आता है । यहां का हर दृश्य अनूठा होता है, अलौकिक होता है, अतुलनीय होता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला होता है ।कानपुर के गंगा मेला में जहां एक और रंगबाजी है, चुहलबाज़ी है, चिकाई है वहीं इसके पीछे राष्ट्रीयता की भावना भी है, 83 वर्ष पुरानी परंपराओं को सहेजने का भाव भी है, अपनी कनपुरिया संस्कृत के प्रति प्रेम भी है ।

बिल्हौर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

» पति का एक्सीडेंट हो जाने के बाद से तनाव में रहने लगी थी कोमल

» करीब एक साल पहले हुआ था विवाह

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर के अरौल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति जब कमरे में पहुंचा तो पत्नी का शव फंदे से लटकता देख दंग रह गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अरौल थाना अध्यक्ष जर्नादन यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के पलिया बुजुर्ग गाव निवासी रंजीत कठेरिया की एक साल पहले कोमल 20 वर्ष से हुई थी। उन्होने बताया कि पूर्व में पति का एक्सीडेंट हो जाने के कारण कोमल काफी समय से मानसिक रुप से बीमार रहने लगी थी। गुरुवार की शाम कोमल ने घर के कमरे में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनो की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा। और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक साल पहले ही कोमल का विवाह रंजीत से हुआ था।

जालसाज़ पीड़िता के शिकंजे में अधिवक्ता

कानपुर कचहरी के अधिवक्ता विवेक शुक्ला को बुरी तरह से फंसाकर किया जा रहा परेशान

» अदृश्य घटना के आधार पर कोतवाली कानपुर में लिखा गया मुकदमा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। हाल ही में स्वराज इंडिया दैनिक अखबार में जालसाज़ पीड़िताओं को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थीं और उन खबरों में सटीक तथ्यों का प्रयोग किया गया था कि किस तरह से कानपुर के अंदर एक ऐसा गिरोह चल रहा है जिसके माध्यम से शहर के अंदर सम्मानित छवि रखने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ थाने या कचहरी में किसी जालसाज़ पीड़िता को पेश करके पहले मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है और फिर लाखों रुपए एंठने के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवा दी जाती है। स्वराज इंडिया की खबरों के बाद मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से सांसद अशोक रावत ने भी इन्हीं घटनाओं से जुड़ा एक प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त कानपुर को दिया था जिसमें उनके द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था। आज फिर जालसाज़ पीड़िताओं से जुड़ा एक गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें कानपुर कचहरी के एक अधिवक्ता विवेक शुक्ला को बुरी तरह से फंसा दिया गया है।

दरोगा मनीष गोस्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला युवक विजय मिश्रा

अधिवक्ता विवेक शुक्ला के द्वारा पुलिस आयुक्त कानपुर को दिया गया शिकायती पत्र

अधिवक्ता के खिलाफ दिए जा चुके हैं 25 प्रार्थना पत्र

अधिवक्ता विवेक शुक्ला का कहना है कि उनके खिलाफ रजनी पालीवाल और उसकी मां शांति देवी के द्वारा कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 25 प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं जिन सभी में पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई जांच में अधिवक्ता विवेक शुक्ला पर लगाया गये सभी आरोप असत्य पाए गए हैं और उसी के आधार पर आख्या रिपोर्ट लगाई गई है। उसके बाद जब अधिवक्ता के द्वारा उसको टारगेट करने वाली महिलाओं को विधिक नोटिस भेजा गया तो इस नोटिस के बदले कानपुर कोतवाली में यह अभियोग पंजीकृत करवाया गया है।

कानपुर कोतवाली में तैनात दरोगा मनीष गोस्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप

इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अनोखी कड़ी जुड़ती नज़र आ रही है वह कानपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक मनीष गोस्वामी से जुड़ती नजर आ रही है जिनके ऊपर विजय मिश्रा नामक युवक के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा विजय मिश्रा नामक युवक का आधार कार्ड इस्तेमाल करके उसकी फोटो कॉपी पर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चश्मदीद गवाह के तौर पर इस मुकदमे में जोड़ा गया है। जबकि जब विजय मिश्रा से जब अधिवक्ता विवेक शुक्ला के द्वारा संपर्क साधकर इस मुकदमे में गवाही देने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो विजय मिश्रा के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि उनका इस मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है वह ना तो दरोगा मनीष गोस्वामी को जानते हैं ना ही रजनी पालीवाल को और विवेक शुक्ला अधिवक्ता से भी वह पहली बार ही मिल रहे हैं। उनके आधार कार्ड का मनीष गोस्वामी दरोगा के द्वारा गलत उपयोग किए जाने का शिकायती पत्र पुलिस आयुक्त कानपुर को उनके द्वारा दिया गया है। इस पूरी घटना को लेकर जब स्वराज इंडिया संवाददाता के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक मनीष गोस्वामी से सवाल किया गया तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया।

बीते दो माह पूर्व 10 जनवरी 2025 को क्राइम नंबर 16/2025 के तौर पर पीड़िता रजनी पालीवाल के द्वारा कानपुर कोतवाली में अधिवक्ता विवेक शुक्ला के ऊपर धारा 352 और 351(1) के तहत एक अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। जिसमें आरोप लगाए जाते हैं कि दोपहर 12ः00 बजे पुलिस लाइन के सामने अधिवक्ता विवेक शुक्ला के द्वारा रजनी पालीवाल और नीरज शुक्ला से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना को लेकर जब स्वराज इंडिया संवाददाता के द्वारा आरोपी अधिवक्ता विवेक शुक्ला से जवाब मांगा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है मैं एक अधिवक्ता हूं अपराधियों को सज़ा दिलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी हैं इसी वजह से मुझे इस तरह के फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है।

पति, बच्चों को छोड़ा, माता-पिता को किया घायल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नौबस्ता थानाक्षेत्र में विवाहित बेटी प्रेमी के साथ रहने लगी तो उसके माता पिता दामाद के साथ खड़े हो गए। बेटी से दामाद के साथ रहने के लिए कहा तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता को पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित पिता थाने पहुंचे और बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

» पति, बच्चों को छोड़ा, माता-पिता को किया घायल; प्रेमी के साथ रहने लगी थी.

» पिता ने बेटी और प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

नौबस्ता निवासी पीड़ित ने बताया कि बेटी की आठ वर्ष पहले शादी की थी। उसके 6 वर्षीय और 3 वर्षीय बेटे हैं।

आरोप लगाया कि पिछले वर्ष इलाके के रहने वाले मोहित ने शादीशुदा बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसके झांसे में आकर बेटी ने पति और बच्चों को छोड़ दिया।

वह हंसपुरम में प्रेमी के साथ रह रही है। उसे समझाने के लिए बुधवार को उनकी पत्नी दामाद के साथ उसके घर गई थी।

वहां बेटी ने दोनों के साथ गालीगलौज की और घर से भगा दिया। वे लोग घर लौटे तो कुछ देर बाद बेटी प्रेमी के साथ घर लौटी और लड़ने लगी।

विरोध करने पर उन्हें पीटा और पत्नी के साथ भी मारपीट की।

जिससे वह घायल हो गए। इस संबंध में नौबस्ता थाने के कार्यवाहक प्रभारी मो. नदीम के अनुसार पिता ने बेटी व प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

जातीय संतुलन साधकर कांग्रेस ने घोषित किए जिलाध्यक्ष

» कानपुर शहर में पवन गुप्ता और कानपुर ग्रामीण में एडवोकेट संदीप शुक्ला को कांग्रेस की कमान

» अपना खोया वजूद तलाश करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक वजूद खडा करने की कोशिश कर रही है। पहले क्षेत्रीय दलों ने जैसे सपा, बसपा ने अपना वर्चस्व जमाया, इससे कांग्रेस को झटका लगा। इसके बाद बीजेपी ने अपना खेल सजाया तो अब सभी दल हासिए पर आ गए हैं। कांग्रेस हाईकमान अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मजबूत गोटियां बिछाने में जुटी है, हालांकि, अभी लडाई बडी है लेकिन दूर नहीं है।

यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी के राजनीतिक केंद्र कानपुर में मंथन शुरू कर दिया है। यहां पर पार्टी ने वैश्य और ब्राम्हण पर दांव लगाकर मजबूत तैयारी के साथ मैदान में आने का प्रयास किया है। देखा जाए तो पार्टी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, दोनों नेता पार्टी की रीति-नीति से भलीभांति वाकिफ हैं और संघर्षशील हैं। कांग्रेस ग्रामीण से जिलाध्यक्ष बनाए गए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य संदीप शुक्ला पेशे से अधिवक्ता हैं। वह लगातार 15 वर्ष से पीसीसी सदस्य हैं। उनके पिता स्व0 अंबिका प्रसाद शुक्ला वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं। इस तरह से संदीप शुक्ला को राजनीति विरासत में मिली हुई है। युवक कांग्रेस के बाद संदीप शुक्ला को तत्कालीन महानगर अध्यक्ष हरिप्रकाश अग्निहोत्री का आर्शीवाद मिला तो कमेटी में महासचिव का पद मिला। वह अपने पिता के पद चिन्हो पर चलकर लगातार जनसमस्याओं एवं मुददों पर मुखर रहते हैं। उन्होने जाजमउ इलाके में पौराणिक ऐतिहासिक राजा ययाति टीले पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला उठाया था, उस समय आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट पर बडी कार्रवाई की गई थी, कई ऐसे मामले आए जिनमें संदीप शुक्ला ने खुलकर विरोध जताया।

वहीं, शहर अध्यक्ष बने पवन गुप्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। वर्ष 2007 में आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडे, 2012 में पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी बनाया। 2008 से 2011 तक भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में चेयरमैन रहे। पवन गुप्ता व्यापारियों के बीच सक्रिय रहकर समस्याओं पर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं।

कार्यकर्ताओं ने घर पहुंच कर संदीप शुक्ला का स्वागत किया

पवन गुप्ता शहर अध्यक्ष

तहसीलदार तिमराज सिंह का हुआ प्रमोशन

स्वराज इंडिया संवाददाता

» बिल्हौर तहसीलदार पद पर तैनात है तिमराज सिंह

» बलिया जनपद में मिली तैनाती

बिल्हौर। गुरुवार को यूपी के 63 तहसीलदारों के लिए अच्छी ख़बर आई। सभी 63 तहसीलदारों को प्रमोट कर दिया गया। तहसीलदार अब एसडीएम का कार्यभार संभालेंगे।

जारी हुई 63 तहसीलदारों की लिस्ट में बिल्हौर तहसीलदार तिमराज सिंह का भी नाम है।

उन्हें बलिया जनपद में तैनाती मिली है। प्रमोशन होकर तहसीलदार से एसडीएम बन जाने की ख़बर आम होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फोन कॉल कर मुबारक़ दी।

सम्पादकीय

वैश्विक प्रयासों से रुकेंगे संगठित अपराध

यह खबर परेशान करने वाली है कि म्यांमार और पूर्वी एशिया के कई देशों से जो संगठित साइबर अपराध संचालित हो रहे हैं, उनके चंगुल में बड़ी संख्या में भारतीय युवा भी हैं। हाल ही में म्यांमार के दुर्गम इलाकों में बनाये गए साइबर अपराधियों के अड्डों से सत्तर भारतीय युवाओं को छुड़ाया गया है। जिनको डरा-धमकाकर भारत में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है साल 2022 के बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि से छह सौ से अधिक भारतीयों को अपराधियों के चंगुल से बचाया जा चुका है। आशंका है कि कई हजार भारतीय युवा म्यांमार समेत विभिन्न देशों में साइबर अपराधियों के अड्डों में जबरन रोके गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय युवा प्रतिभाएं दलालों की साजिश से संगठित साइबर अपराध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के चंगुल में फंस जाती हैं। विडंबना ही है कि हम अपने युवाओं को न तो रोजगार दे पा रहे हैं और न ही विदेशों में अपना भविष्य संवारने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचा पा रहे हैं। आखिर हमारी एजेंसियां ऐसी धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि युवा अपनी जमीन बेचकर व कर्ज उठाकर विदेश जाते हैं, लेकिन एजेंटों की धोखाधड़ी से वे साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंस जाते हैं। दरअसल, साइबर अपराधियों का मकड़जाल इतना मजबूत हो चुका है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उन पर नियंत्रण कर पाना संभव न होगा। ऐसे वक्त में जब साइबर अपराधियों का नेटवर्क दुनिया की आर्थिकी को चूना लगा रहा है, मिल-जुलकर इनके खिलाफ अभियान चलाना वक्त की जरूरत है। निश्चित रूप से यह एक विकट संकट है, जिसे दुनिया के देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह जानते हुए कि साइबर अपराधियों का संगठन लगातार ताकतवर होता जा रहा है और वे समानांतर काली अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।दरअसल, हो यह रहा है कि देश-दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वे सुनहरे सपने दिखाकर बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं। उन्हें जगह कोई और बतायी जाती है और अंततः साइबर अपराधियों के अड्डों पर पहुंचा दिया जाता है। युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। हाल ही में जिन सत्तर भारतीयों को म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, उसमें म्यांमार के सीमा सुरक्षा बल की बड़ी भूमिका रही है। इन मुक्त कराए गए भारतीयों में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,यूपी व राजस्थान आदि राज्यों के लोग थे। इसी तरह म्यांमार व अन्य पूर्वी एशिया के देशों में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे हुए भारतीयों को मुक्त कराने के लिए इन देशों की सरकारों से सहयोग मांगा जाना चाहिए।

नेताओं को बौना बना रही है संकीर्णता

विश्वनाथ सचदेव

भूल जाना आदमी की फितरत है। आदमी अच्छी बातें भी भूल जाता है, और बुरी बातें भी। बुरी बातों को भूल जाना तो अच्छी बात है, पर कुछ अच्छी बातों को भूल जाना अच्छा नहीं है। ऐसी ही अच्छी बात वर्ष 1965 की भारत-पाक लड़ाई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। पता नहीं कितनों को याद होगा कि उस लड़ाई में अब्दुल हमीद नाम का एक भारतीय सैनिक भी था, जिसने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करके हमारी जीत को संभव बना दिया था। तब क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने हमें जिता तो दिया, पर अपनी जान की कीमत देकर। कृतज्ञ राष्ट्र ने उस जांबाज शहीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था।इस शहीद का जन्म उत्तर प्रदेश के दुल्लहपुर नामक गांव में हुआ था।

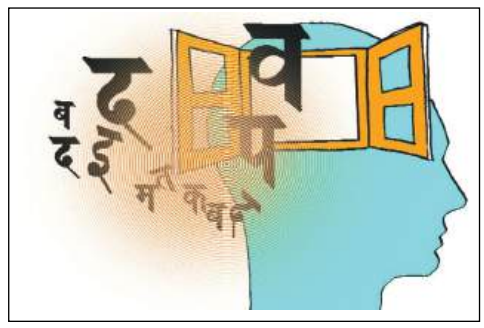

गांव वालों ने अपने इस सपूत के सम्मान में गांव के स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा था। बरसों से यह नाम गांव की एक पहचान बना हुआ था। कुछ ही अर्सा पहले स्कूल का नाम बदल दिया गया- नया नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामपुर कर दिया गया। क्यों बदला गया, किसी ने नहीं बताया। बस बदल दिया।नाम बदलने की यह अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मऊ को जोड़ने वाली सड़क पर बने एक द्वार का नाम ऐसे ही बदल दिया गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम का यह द्वार बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया। मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर बने एक कॉलेज की दीवारें गिरा देने वाला समाचार भी हाल ही का है। यह बात भुला दी गयी कि मुख्तार अहमद अंसारी कभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान यह पद संभालने वाले अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों में थे।नाम बदलने का यह सिलसिला अब नया नहीं लगता। चौंकाता भी नहीं। पिछले दो दशकों में न जाने कितनी जगह के नाम बदले गये हैं। ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। औरंगजेब ने भले ही अत्याचार किये हों, पर वह वर्षों तक इस देश में शासन करता रहा, यह हकीकत तो अपनी जगह है। फिर, हम क्यों भूल जाते हैं कि किसी औरंगजेब को याद करने का मतलब उन अत्याचारों की भी याद दिलाता है, जिनसे हमारे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। ऐसी बातों को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्हें दुहराया न जाये।बहरहाल, जगहों के नाम बदलना कोई नयी बात नहीं है। पर इस प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता को भी समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहरों आदि के नाम बदलने का काम सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक आदि पार्टियों ने भी अपने-अपने शासन काल में इस तरह नाम बदले हैं। सच्चाई यह है कि अक्सर यह बदलाव राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम होते हैं। अपने-अपने हितों के लिए हमारे राजनीतिक दल अक्सर जगहों का नाम बदलना एक आसान मार्ग समझ लेते हैं। लेकिन, यह आसान मार्ग अक्सर राष्ट्रीय हितों से भटका देता है, इस बात को भुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की जो कवायद इस समय चल रही है वह उन सबके लिए चिंता का विषय होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। सन? 2012 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के नाम बदले गये थे?

बढ़ गया है विसंगतियों को प्रश्रय का खतरा

उत्तराखंड में नया भूमि कानून

जयसिंह रावत

अब तक गैर-कृषक के लिये जमीनों की खरीद पर बंदिशें थीं, लेकिन अब जिसकी भी उत्तराखंड में अचल सम्पत्तियां हैं उनके लिये भी किसानों की जमीनें खरीदने का रास्ता निकल गया है।उत्तराखंड की धामी सरकार ने नया भूमि कानून पास तो करा दिया है, लेकिन इस कानून से पहाड़वासियों की नाउम्मीदी ज्यादा बढ़ गयी है। सरकारी पक्ष नये कानून को सख्त बताकर प्रचारित कर रहा है, लेकिन गरीब कास्तकारों के पुरखों की जमीनों के भू-खोरों, धन्नासेठों और गैर-कृषकों द्वारा हड़पने के नये रास्ते खुले बताते हैं।

हालांकि, किसी देशवासी के लिये बाहरी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है फिर भी जिन लोगों को बाहरी माना जा रहा है, उनके लिये उत्तराखंड में जमीनें खरीदने के लिये पिछले दरवाजे खुले हैं। अब तक गैर-कृषक के लिये जमीनों की खरीद पर बंदिशें थीं, लेकिन अब जिसकी भी उत्तराखंड में अचल सम्पत्तियां हैं उनके लिये भी किसानों की जमीनें खरीदने का रास्ता निकल गया है मगर नगर निकाय चाहे कहीं की भी हों, उन्हें इस कानून से मुक्त कर दिया। विधि विशेषज्ञ और भू-कानून के लिए आन्दोलन करने वाले इसे प्रदेश की जनता के साथ छलावा बता रहे हैं।नये कानून की धारा दो में कहा गया है कि 'नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी

परिषद क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह कानून सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा।' उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोग गांव छोड़कर आसपास के कस्बों में बहुत तेजी से बस रहे हैं इन्हीं नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सर्वाधिक खरीद-फरोख्त होती है।शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उद्यान, पर्यटन, के लिये निजी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था आदि के लिए भूमि का अन्तरण पर पहले भी प्रतिबंध नहीं था। नयी व्यवस्था में अगर भूमि का अन्तरण जनहित में है तो जमीन चाहने वालों का वास्तविक आंकलन कर भूमि अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। साथ ही अन्तरण अनुमति से पूर्व सम्बंधित विभागों द्वारा निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन तथा प्लांट और मशीनरी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव का आंकलन करते हुए भूमि अनिवार्यता प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष या एक रैंक नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि अन्तरण की अनुमति केवल हरिद्वार और उधमसिंह नगर में दी जायेगी। अगर भूमि की खरीद-फरोख्त की बंदिशें शेष 11 जिलों के लिये हैं तो उन पहाड़ी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र इन दो जिलों की तरह कानून से मुक्त क्यों कर दिये गये? नये कानून में व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई व्यक्ति जो धारा 129 के तहत उत्तराखंड का खातेदार न हो तो उसे रजिस्ट्रार के सामने शपथपत्र देना होगा कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने आवासीय उद्देश्य के लिये अपने जीवनकाल में 250 वर्गमीटर जमीन नहीं खरीदी है। सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कानून का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी 250 वर्गमीटर जमीनें खरीद ली हैं। जबकि मूल कानून में व्यवस्था थी कि एक परिवार एक ही बार जमीन खरीद सकेगा।

वन पॉट पास्ता, स्वाद का मज़ेदार रास्ता!

अगर आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रही हैं, तो आपको एक बार वन पॉट पास्ता की रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। यह यूनिक स्टाइल पास्ता रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इस डिश को बनाना भी बहुत आसान है।

अधिकतर घरों में शाम के समय भूख लगने पर पास्ता, नूडल्स और माइक्रोनी खाना पसंद करते हैं। यह चीजें सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। वहीं ये चीजें झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। साथ ही इन चीजों को खाने से पेट भी काफी देर तक भरा महसूस होता है। ऐसे में अगर आपको पास्ता, नूडल्स और माइक्रोनी खाना पसंद है, तो आज हम आपके साथ कुछ यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं।

आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वह पास्ता की इटेलियन डिश है। जिसको आज के समय में हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि इस डिश को तैयार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रही हैं, तो आपको एक बार वन पॉट पास्ता की रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। यह यूनिक स्टाइल पास्ता रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इस डिश को बनाना भी बहुत आसान है। सामग्री पास्ता- 1 कप, ऑलिव आयल- 2 टेबलस्पून, लहसुन-1 टेबलस्पून

प्याज-1/4 कप, मशरूम- 200 ग्राम काली मिर्च-आधा टेबलस्पून, नमक-स्वादानुसार, दूध-2 कप, चीज स्लाइस-2, बेबी टोमेटो-4-5, पालक-1 बंच, बेसिल के पत्ते-4-5

ऐसे बनाएं वन शॉट पास्ता

सबसे पहले एक गैस पर पैन रखें और उसमें ऑलिव ऑयल डालकर गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए, तो उसमें प्याज और लहसुन डालकर हल्का ब्राउन होकर भूनें। फिर इसमें मशरूम, दो कप पानी और दूध डालकर उबलने के लिए रख दें। अब ऊपर से नमक और काली मिर्च डालें। इसके बाद इसमें स्पैगटी पास्ता डालकर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएं। फिर इसको खोलकर ऊपर से पालक, चेरी टोमेटो और बेसिल के पत्ते डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसको दोबारा ढककर 2-3 मिनट तक पकने दें। जब यह पक जाए, तो इसको खोलकर ऊपर से स्लाइस चीज रखकर चलाएं और गर्मागर्म सर्व करें।

नवरात्रि में करें मां के दर्शन, पूरी होंगी सारी मनोकामनाएं!

नवरात्रि में माँ दुर्गा के दर्शन से पाएं आशीर्वाद, पूरी होंगी मुरादें

पर्यटन स्थल

मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरु होने जा रही हैं। इस दौरान लोग माता के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर है, जो भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। इस लेख हम आपको 5 बड़े मंदिरों के बारे बता रहे हैं, जहा आप दर्शन के लिए जा सकते हैं।

नवरात्रि में माँ दुर्गा के दर्शन करें, पाएं आशीर्वाद, शुभ फल, सुख-समृद्धि, शांति, शक्ति, सौभाग्य, सफलता, आनंद, प्रेम और पूरी करें सभी मुरादें!

हिंदू धर्म में चार बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि मानी जाती है, जो साधु-संतों के लिए होती है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि भक्तों के लिए होते हैं, यह साल में दो बार आती हैं। इस साल 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरु होने जा रही हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरुपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन मां दुर्गा के दर्शन के लिए अलग-अलग मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। इस लेख हम आपको बताने जा रहे हैं देवी मां के मंदिरों के बारे में, जहां दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आप जाएं इन 5 मंदिरों में दर्शन करने के लिए।

वैष्णो देवी मंदिर

जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। भारत के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है वैष्णो देवी मंदिर, यहां हर साल लांखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को सुंदर नजारों से होकर ले जाता है और कई लोगों का मानना है कि जब देवी मां बुलाती हैं, तभी तीर्थयात्रा पूरी होती है। भक्तों के दुख दूर होते हैं और हर एक मुराद पूरी होती है।

दक्षिणेश्वर काली मंदिर

पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर काफ़ी फेमस है। यह मां दुर्गा के नौ स्वरुपों में से एक देवी काली को समर्पित है। इस मंदिर में आध्यात्मिक माहौल के लिए काफी प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं।

कामाख्या मंदिर

कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर भारत का सबसे पुराने देवी दुर्गा मंदिरों में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता सती के योनि का भाग इस स्थान पर गिरा था। मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। भारत में इसे सबसे जरुरी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी मंदिर

गुजरात में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है अंबाजी मंदिर। यह मंदिर देवी अंबा को समर्पित है। अरावली पहाड़ियों पर स्थित अंबाजी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर को सुंदर तरीके से सजाया जाता है।

चामुंडा देवी मंदिर

हिमाचल प्रदेश में स्थित चामुंडा देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। यहां पर लोग माता रानी का आशीर्वाद और शांति पाने के लिए आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहां पर भीड़ देखने को मिल सकती है। चामुंडा देवी अपने भक्तों की सभी मानोकामना पूर्ण होती है।

नेचुरल नुस्खे का कमाल, त्वचा दिखेगी हरदम जवां

नेचुरल फेस मास्क से पाएं जवां और दमकती त्वचा, बढ़ती उम्र भी नहीं डाल पाएगी असर!

आजकल मार्केट में कई महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन इसकी बजाय आप इन 4 घरेलू चीजों के इस्तेमाल से घर पर एक एंटी-एजिंग फेस मास्क बना सकते हैं। यह फेस मास्क हमारी स्किन को जवां और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है।

उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी स्किन पर भी कई तरह के बदलाव आते हैं। यह बदलाव जैसे स्किन का ढीलापन, झुर्रियां, काले धब्बे और स्किन की अन्य समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि मार्केट में आजकल कई महंगे-महंगे एंटी-एजिंग मौजूद होते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट में केमिकल्स होते हैं। जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर आप इन महंगे प्रोडक्ट की जगह घरेलू उपायों की मदद लेते हैं, तो यह न सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि इससे स्किन भी यंग नजर आती हैं। वैसे तो एंटी-एजिंग के कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन ढीली पड़ जाती है। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें स्किन की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इससे स्किन में उम्र बढ़ने के लक्षण जैसे सन डैमेज, डार्क स्पॉट्स, झुर्रियों और फाइन लाइन्स दिखाई देने लगते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के समय हार्मोनल बदलाव की वजह से स्किन में ढीलापन और सूखापन आ सकता है। स्किन को स्वस्थ बनाए रखने में पानी काफी महत्वपूर्ण होता है। जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखाई दे सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी सहायता करते हैं। साथ ही यह स्किन में प्राकृतिक चमक आती है। वहीं यह झुर्रियों और फाइन लाइन को भी कम करती है। साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ती है।

फ्लेक्स सीड

फ्लेक्स सीड्स को अलसी का बीज भी कहते हैं। यह एंटी-एजिंग के लिए बेहतरीन प्राकृतिक सामग्री है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर पाए जाते हैं। जो स्किन को अंदर से पोषण देने के साथ जवां बनाए रखने में भी मदद करता है।

ऐसे करें इस्तेमाल, फ्लेक्स सीड्स को अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। आप फ्लेक्स सीड्स के पाउडर को अन्य सामग्री के साथ मिलाकर फेस मास्क के रूप में अप्लाई करें। चावल का आटा बता दें कि चावल का आटा हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। चावल के आटे में एंटी-एजिंग गुण पाए जाते हैं, जोकि स्किन को मुलायम बनाते हैं। चावल के आटे में पारा और सैपोनिन स्किन को टाइट करने में मदद करता है और उम्र बढ़ने के असर को धीमा करता है। स्किन के डेड सेल्स को हटाकर उसको साफ और निखरा हुआ बनाता है।

ऐसे करें इस्तेमाल

नियमित रूप से चावल के आटे को फेस मास्क में मिलाकर लगाने से स्किन पर नेचुरल चमक आती है। साथ ही यह स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है। विटामिन-ई विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है। यह स्किन को रिपेयरिंग और रीजेनरेशन को बढ़ावा देता है। विटामिन ई स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और नमी को बनाए रखता है। विटामिन ई झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। विटामिन ई स्किन को सूर्य के हानिकारक प्रभावों से बचाता है और त्वचा की रंगत को निखारता है।

गंगा मेला में मिट जाते हैं हर गिले शिकवे...

निर्मल तिवारी / स्वराज इंडिया

» स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं इस परंपरा के तार

» सरसैया घाट पर आयोजित हुए मेले में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं

कानपुर। कहा जाता है वर्ष 1942 में होली के पर्व के समय अंग्रेजों ने निषेधाज्ञा लगा दी थी। इसके विरोध में हटिया क्षेत्र के कुछ युवकों ने होलिका दहन वाले दिन रज्जन बाबू पार्क में तिरंगा फहरा दिया। जिसकी भनक लगते ही तत्कालीन अंग्रेज प्रशासन ने हटिया क्षेत्र से कुछ युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की बात फैलते ही पूरा कानपुर विरोध पर उतर आया। होली नहीं खेली गई और दुकान कारखाने मिलें सभी में बंदी हो गई ।आखिर में तत्कालीन अंग्रेज हुक्मरानों को झुकना पड़ा और लगभग सात दिन बाद सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को रिहा करना पड़ा। उस दिन अनुराधा नक्षत्र था। क्रांतिकारियों को लेने के लिए, उनकी अगवानी के लिए जिला कारागार के निकट हजारों कनपुरिया पहुंच गए और वहां जमकर होली खेली गई और फिर इन क्रांतिकारियों को जुलूस के रूप में हटिया के रज्जन बाबू पार्क लाया गया ।उस दिन खेली गई होली कानपुर की परंपरा बन गई। तब से आज तक कानपुर में बहुदिवसीय होली खेलने की परंपरा कायम है।कानपुर का गंगा मेला प्रतीक है कनपुरिया संस्कृति का, प्रतीक है कानपुर के पूर्वजों की राष्ट्रभक्ति का, प्रतीक है स्वतंत्रता आंदोलन में कानपुर की अग्रणी भूमिका का, प्रतीक है कानपुर के बगावती तेवरों का, प्रतीक है कानपुर की जिजीविषा का, प्रतीक है कानपुर के हौसलों का, प्रतीक है कानपुर के तेवरों का, प्रतीक है कानपुर के मस्त मौला खिलंदड़ स्वभाव का और प्रतीक है परंपराओं को सहेजने की कानपुर की प्रवृत्ति का।

पुखरायां में लापरवाही से प्रसूता की मौत, हंगामा

अस्पताल में मौजूद रहे दुखी परिजन

अस्पताल की फाइल फोटो

प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात । पटेल चौक पुखरायां के पास स्थित प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई । परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया । सूचना पर भोगनीपुर इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और परिवार को समझाया।

सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव निवासी रोहित सविता ने बताया कि उसने अपनी पत्नी राजकुमारी 27 वर्ष को बुधवार को पटेल चौक स्थित अंनिकल्प हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था जहां बुधवार को ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म हुआ और ऑपरेशन के आधा घंटे बाद तबीयत बिगड़ गई मौजूद डॉक्टर तुरंत अकबरपुर अस्पताल में रेफर किया गया। हालत खराब होने के कारण कानपुर सिटी हॉस्पिटल ले गए। जहां इलाज के दौरान राजकुमारी सविता की मौत हो गई ।

राजकुमारी के पति रोहित वह बहनाई नितिन व अमित कुमार शव को लेकर पुखरायां अस्पताल पहुंचे और लापरवाही से इलाज का आरोप लगाकर हंगामा काटने लगे । सूचना पर भोगनीपुर थाने के अति निरीक्षक जितेन्द्र सिंह व चौकी इंचार्ज जितेन्द्र तिवारी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को समझ कर मामला शांत किया।

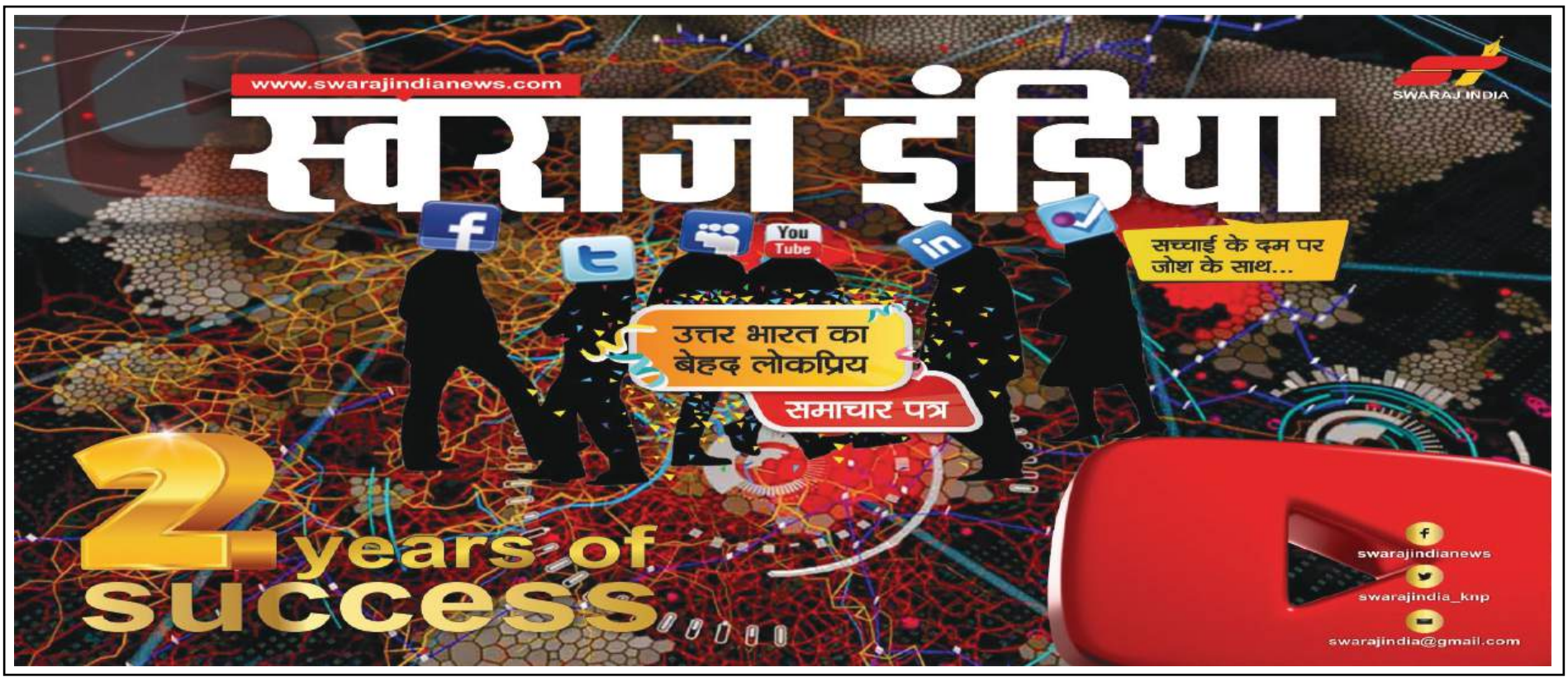

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | **प्रधान संपादक रतन प्रकाश सिंह (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)**

40 वर्षीय विधवा की घर के अंदर हत्या

पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भेजा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात । भोगनीपुर थाना क्षेत्र के गुरगांव गांव में रात में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय विधवा महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है

गुरगांव निवासी राजेश कुमार सचान उर्फ कल्लू 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी घर पर राजेश सचान की पत्नी कालिंदी सचान 40 वर्ष रहती थी उसके दोनों बच्चे सागर व हिमांशी अपने ननिहाल मकरंदापुर

में रहकर पढ़ाई करते थे। गुरुवार को रात को लड़का सागर भी अपनी मां के पास गुरगांव में आया था दोनों घर के अंदर सो रहे थे तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर कालिंदी सचान की गला घोटकर हत्या कर दी लड़के ने जब देखा तो उसने अपने मामा को फोन किया मामा ने भोगनीपुर थाने में घटना की सूचना दी ।मौके पर कोतवाल अंजन सिंह व क्षेत्राधिकारी संजय सिंह ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की वह कालिंदी सचान का मोबाइल भी बरामद किया है

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है कोतवाल अंजन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर घटना की सही जानकारी हो सकेगी।

बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियां करवाएं

» हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का किया गया आयोजन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड अमरौधा में नेशनल इंटर कॉलेज पुखरायां में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विकासखंड के 12 न्याय पंचायत के वाल वाटिका से कक्षा 2 के निपुण बच्चे नोडल शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को शामिल किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी ईश्वरकांत मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। ए आर पी दिनेश बाबू द्वारा बताया गया की 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को भाषा और गणित में कक्षा और उम्र के अनुसार निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो दक्षताएं दी गई हैं। उनको हासिल करना प्राथमिक विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। जिसमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका के रूप में किया जाएगा। विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की टी एल एम सामग्री भेजी जा रही है नोडल शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिलकर बच्चों को उसे टीएलएम से परिचित कराए। जिससे बच्चों का भाषा गणित के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो सके । आरपी रवि द्विवेदी द्वारा बताया गया कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियों एवं खेल-खेल के माध्यम से बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से गतिविधियां कराई जाए जिससे बच्चे विद्यालय में ठहरे बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने के अवसर दें बच्चे विद्यालय में आए अपने आप को आनंद महसूस करें अंत में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया की शैक्षिक सत्र 2024-25 में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन करें और जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं वह अपने बच्चों को आधार बी आर सी भोगनीपुर में निशुल्क बन रहे हैं बच्चों को भेजकर उनके आधार अनिवार्य रूप से बनवा ले जो बच्चे शेष रह गए हैं। डीबीटी के अंतर्गत विभाग द्वारा धनराशि मिलनी थी उन बच्चों का डीबीटी 31 मार्च से पूर्व अनिवार्य रूप से कर दें, जिससे बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि विभाग द्वाराभेजी जा सके। जिन बच्चों ने कक्षा के अनुसार दक्षता हासिल की है उन बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। सभी बच्चे पुरस्कार पाकर प्रसन्न हुए । हमारा आंगन हमारे कार्यक्रम में नोडल शिक्षक विमल सचान, योगेंद्र कुमार त्रिवेदी, अरविंद कुमार यादव, लोकेश द्विवेदी, सतीश यादव, आलोक कुमार, पवनेश पटेल, सुरेश बाबू, सुदीप सचान, प्रमिला सचान, सबिया परवीन और अभिभावक बच्चे उपस्थित रहे।

चहेतों को जमीन आवंटन करने में फंसे एसडीएम मिल्कीपुर

अपर मुख्य सचिव करेंगे एसडीएम के खिलाफ मामले की जांच

» पहले से ही कई विवादों में आ चुके हैं एसडीएम मिल्कीपुर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। पहले भी अपनी कार्य प्रणाली से विवाद में चल रहे एस डी एम मिल्कीपुर राजीव रत्न सिंह की परेशानी और बढ़ने वाली है। उनके खिलाफ जांच का दायरा और बढ़ गया है। अपने चहेतों को गलत ढंग से भूमि आवंटन करने के खिलाफ अब प्रदेश सरकार ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रत्न के खिलाफ भूमि घोटाले की जांच अब अपर मुख्य सचिव करेंगे।

मिल्कीपुर तहसील में तैनाती के बाद एसडीएम ने अपने खास लोगों को धारा 67 का लाभ देकर अनुचित रूप से भूमि आवंटन की है। इसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह शिकायत किसान यूनियन के नेता रमेश तिवारी ने प्रधानमंत्री जनसुनवाई पर दर्ज कराई है।

मिल्कीपुर तहसील के तुलापुर गांव निवासी भारतीय किसान यूनियन के नेता रमेश तिवारी द्वारा प्रधानमंत्री जनसुनवाई पर दी गई शिकायत में कहा गया है कि धारा 67 ए का लाभ देकर उप

जिलाधिकारी मिल्कीपुर राजीव रत्न सिंह ने अपने मातहतों को भूमि का आवंटन कर दिया है। जिसमें नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई गई है शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि, मिल्कीपुर तहसील में लेखपाल और कानूनगो के ट्रांसफर के लिए एक संविदा कर्मी के इशारे पर एसडीएम मिल्कीपुर अनियमित ढंग से कार्य कर रहे हैं। संविदा कर्मी अमित श्रीवास्तव को रखकर मोटी रकम लेकर करवाते हैं लेखपाल वा कानूनगो का ट्रांसफर। कुछ दिन पहले एक दलित का घर बिना किसी नोटिस के जमींदोज कर दिया था।

जबकि उस जमीन पर सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जिसके बाद सचिव राजस्व परिषद को जांच अधिकारी नामित किया गया है। घोटालों की बात की जाए तो एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रत्न का घोटालों एवं विवादों से पुराना नाता रहा है।

एसडीएम से जुड़े हैं कई और विवाद

गत दिनों वार एसोसिएशन मिल्कीपुर के सदस्यों के कामकाज को एसडीएम ने नौटंकी बताया था। जिसके बाद वकीलों ने उनके खिलाफ जमकर धरना-प्रदर्शन किया था।वाद में माफी मांगने पर मामला हुआ शांत हुआ था। वर्ष 2018 में आजमगढ़ में बतौर समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए भी उन पर मनमानी एवं करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था। आरोपों के बाद निलंबित कर दिए गए थे। अब देखना है कि राजस्व परिषद की जांच में क्या तथ्य सामने आता है ,एवं क्या कार्रवाई होती है। पाराखानी गांव के कुर्मी का पुरवा में बिना किसी लिखित आदेश दलित महिला का घर जमींदोज करने के मामले ने एसडीएम राजीव रत्न के खिलाफ विरोध की आग भड़का दी है। देखना है योगी सरकार विवादित एसडीएम पर तलवार चला पाती है, या फिर पहले की तरह सरकार उनको अभयदान दे देती है।

संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई का कार्य पूरा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सप्ताह का दिया था समय

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

संभल (उप्र)। संभल की जामा मस्जिद में शुक्रवार को रंगाई–पुताई का कार्य पूरा हो गया। इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत के आदेश के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। जामा मस्जिद समिति के सचिव मसूद फारूकी ने बताया कि रंगाई पुताई का काम पूरा हो गया है और लाइटिंग का काम चल रहा है जिसके आज पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, इसके लिए उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह की समय सीमा दी थी और हमें विश्वास है कि काम

निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की देखरेख में यह कार्य रविवार से चल रहा है। मस्जिद प्रबंधन ने पहले ढांचे के चारों ओर सफेदी तथा अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की अनुमति मांगी थी। मुगलकालीन मस्जिद में सफेदी उस समय की गई है जब इसे लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। एक याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया था। पिछले साल नवंबर में एक स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिए जाने के बाद संभल में दंगे भड़क उठे थे।

सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गयी थी ।

1 अप्रैल से शुरू होगा निजी स्कूलों का सालाना लूट समारोह

» निजी स्कूलों की मनमानी पर क्यों चुप रहते है जनप्रतिनिधि

» एडमिशन फॉर्म, ड्रेस, किताब, स्कूली वाहन और परीक्षा शुल्क के रूप में होती है वसूली

» सांसद विधायक नौकरशाहो के साथ जनप्रतिनिधियों के हैं स्कूल ?

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। वर्ष बदलते हैं लेकिन हालात नहीं बदले। फीस और किताबों के सेट के नाम पर लुटेरों के जज्बात भी नहीं बदले हैं। महंगाई के नाम पर कॉपी किताबों की कीमतें हर वर्ष हद से ज्यादा बढ़ाई जाती हैं। हर चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जात-पात जैसे तमाम मुद्दे उठते है। वादे होते हैं, वादे होते हैं, कुछ पूरे तो कुछ अधूरे रह जाते है, लेकिन किसी भी दल ने अभिभावकों के उस दर्द को साझा करने की कोशिश नहीं की जो उन्हें प्राइवेट स्कूलों से मिलता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को चौपट मानते हुए अभिभावक निजी स्कूलों का रुख करते हैं। इन्हें स्कूल की जगह दुकान कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। एडमिशन फॉर्म से शुरू होने वाली वसूली ड्रेस, किताब, स्कूली वाहन और परीक्षा शुल्क के रूप में सालों भर जारी रहती है। हर साल 15 से 20 फीसद बढ़ोतरी और तीन से चार महीने की एडवांस फीस जमा करवाना तो आम बात है। इसके बाद भी ज्यादा कमीशन देने वाले प्रकाशक की पुस्तकें और मर्जी की ड्रेस। बच्चों के भविष्य को देखकर हर अभिभावक इस मनमानी को सहते हुए सिस्टम को कोसता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने कभी इस दर्द पर मरहम लगाने का प्रयास नहीं किया। प्रस्तुत है अयोध्या से स्वराज इण्डिया संवाददाता समीर शाही की रपट।

प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को ताक पर रखते हैं। यहां तो कई स्कूल कई महीनों की फीस एडवांस लेने के साथ ही एडमिशन फीस के नाम पर डोनेशन भी लेते हैं। अयोध्या जनपद के सभी नामी गिरामी स्कूलो सहित अलग-अलग स्थानों में यही स्थिति बनी हुई है।

अपने मनचाहे प्रकाशक की किताबें कमीशन के चक्कर में चलाई जाती हैं तो ड्रेस भी मनमानी जगह से दिलाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष एडमिशन फीस कराने के साथ-साथ मासिक फीस में वृद्धि कर दी जाती है। इस ओर ना तो किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा आवाज उठाया जा रहा है और ना ही प्रशासन ही सक्रिय है। जिले में शिक्षा विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन लिए ही कई विद्यालय संचालित हो रहे है। जिले में जितने स्कूल है उतने ही प्रकाशकों की किताबें अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। सरकार ने भले ही एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का निर्देश दिया हो, लेकिन आज भी निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रकाशकों की किताबें ही पढ़ाई जा रही है। फीस, ड्रेस और किताबों के नाम पर लूट जारी है। निजी विद्यालयों में अभिभावक फीस, तो बच्चे बस्ते के बोझ से दब रहते हैं।

मार्च अप्रैल का महीना, बच्चों के मां-बाप के जेब कटने का महीना होता है। आमतौर पर जब कोई आपकी जेब काटता है तो आप चोर-चोर चिल्लाते हैं, लेकिन इन दो महीनों में जब मां-बाप की जेब कटती है तो वो स्कूल-स्कूल चिल्लाते हैं। किसी जेबकतरे की शिकायत आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। लेकिन जेब काटने वाले स्कूलों की आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जेबकतरे को पुलिस पकड़कर जेल में भी डाल दे, आपका कुछ पैसा भी दिलवा दे, लेकिन स्कूलों पर कोई हाथ नहीं डालता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हैं। ऐसा इसलिए है कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक, नौकरी पेशा से लेकर व्यापारी तक, सभी के बच्चे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, उनके बच्चों को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, उनके बच्चे के साथ भेदभाव ना शुरु कर दिया जाए, इस डर से सब चुप रहते हैं। और चुप्पी ही स्कूली जेबकतरों की शक्ति है।प्राइवेट स्कूली शिक्षा की बातें मतलब ये है कि एक ही परिवार के अगर दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हों, तो स्कूल उन्हें किताबें शेयर करने की इजाज़त नहीं देता है। यानी 7वीं क्लास में पढ़ने वाली कोई बच्ची, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली अपनी बड़ी बहन की किताबें इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको 8वीं की नई चमचमाती किताबें ही लेनी होंगी। और जैसा की हम कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूली शिक्षा की दुनिया में कुछ बातें सत्य है, उसमें से एक ये भी है कि किताबें छापने वाली कंपनियां और प्राइवेट स्कूलों में गहरे करीबी संबंध होते हैं, कई बार स्कूलों के ही अपने पब्लिशिंग हाउस भी होते हैं।

प्राइवेट स्कूल..कॉपी किताबों के सेट खरीदने के लिए एक पर्ची और साथ में कॉपी-किताबों की लिस्ट देता है

» पर्ची पर पहले से निर्धारित एक खास विशेष दुकान का नाम लिखा होता है।

» आप उस दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को वो पर्ची देते हैं।

» पर्ची लेकर दुकानदार आपको एक बैग थमा देता है, इस बैग में पहले ही वो सारी कॉपी-किताबें और स्टेशनरी मौजूद होती है जो स्कूल ने अपने लिस्ट में लिखी थी।

» ना आप दुकानदार से कुछ बोलते हैं, ना दुकानदार आपसे कुछ कहता है। पर्ची,पैसों और किताबों का लेनदेन हो जाता है काम खत्म।

कई बार अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों की ओर से ऐसे संकेत दिए जाते हैं, कि अगर वो फीस या स्टेशनरी संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों का एडमिशन कहीं और करवा सकते हैं। बस यही बात माता पिता के डर की वजह बनता है। उन्हें मालूम है कि प्राइवेट स्कूल्स के संबंध बड़े-बड़े व्यापारी घरानों से भी होते हैं। ऐसे में अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ना तो कार्रवाई की उम्मीद होती है, ना ही कड़े नियम कानून बनने की उम्मीद होती है।

प्राइवेट स्कूल भी बेधड़क वही करते हैं जिससे उनकी कमाई हो सके। देश में शिक्षा के हालात ऐसे है कि मां-बाप को अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की इसी मजबूरी का लाभ उठाते हैं।

सरकारी स्कूलों की दुर्दशा से फल-फूल रहा धंधा

अधिसंख्य लोगों का मानना है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह धंधा फल फूल रहा है। अब शिक्षा केंद्रों की जगह किसी दुकान का स्वरूप लेते जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता। डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, जूतों, कपड़ों के मनमाने दाम लगाकर स्कूल प्रशासन अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। अधिकतर स्कूल किताबों के लिए दुकान तय करते हैं। इतना ही नहीं स्कूल इवेंट्स के नाम पर भी बार-बार वसूली की जाती है। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों की अनदेखी से अभिभावकों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है।

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नहीं होता नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के निजी विद्यालयों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन लेनी है। इसके तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती है। बावजूद इसके विद्यालयों में इस नियम के तहत बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाता है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। अभिभावक स्कूल में प्रवेश से लेकर परीक्षा परिणाम मिलने तक शोषण का शिकार होते हैं। लेकिन कभी नहीं दिखा किजनप्रतिनिधियों ने अपने ही मतदाताओं की इस शोषण की कहानी पर दो शब्द भी कहे हो। हर अभिभावक की सोच बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की है। इसी मंशा से जहां इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं। बात नेताओं और जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते। न अपने क्षेत्र में और न ही सदन में किसी ने यह पीड़ा उठाई। वजह यह है कि ज्यादातर बड़े निजी स्कूलों के मालिक नेता विधायक जनप्रतिनिधि और बड़े नौकरशाह है। ऐसे में स्कूलों के शोषण का यह मुद्दा गायब है।

राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं: मुख्यमंत्री

अयोध्या: सीएम योगी ने युवाओं को वितरित किया 47 करोड़ का ऋण

» टाइमलेस अयोध्या कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी।

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया।

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामनगरी पहंचे। वह सुबह साढ़े नौ बजे हेलीकाप्टर से रामकथा पार्क पहुंचे। मुख्यमंत्री राजसदन में अयोध्या राजपरिवार के तत्वाधान में आयोजित 'टाइमलेस अयोध्या' कार्यक्रम का सुबह 11 बजे उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रामलला व बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। टाइमलेस अयोध्या का उद्घाटन करने के उपरांत रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। दोपहर 12 बजे आयुक्त कार्यालय सभागार में वह समीक्षा बैठक की। दोपहर एक बजकर 25 मिनट से अमृत बाटलर्स में आयोजित प्लांट विस्तारीकरण का लोकार्पण किया।

रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी तीन पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है उस नौकरशाही में बड़ा वर्ग ऐसा था, जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने पर विवाद खड़ा हो जाएगा।

हमने कहा कि विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने के आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा था कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कि कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के उदय के साथ ही अब दुनिया नये भारत की बात करने लगी है। उत्तर प्रदेश और भारत के लोग दुनिया में कहीं जाते थे तो खुद को भारतीय कहने पर थोड़ा संकोच करते थे पर अब गर्व से खुद को भारतीय कहते हैं क्योंकि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी तरह यूपी के लोग कहीं बाहर जाने पर खुद को उत्तर प्रदेश का बताने पर संकोच करते थे पर अब वो गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बताते हैं।

मुख्यमंत्री योगी रामकथा पार्क पहुंचे और मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को 47 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया और उनसे उद्यम अपनाने की अपील की। सीएम योगी ने महाराजा पैलेस राज सदन में दो दिनों तक चलने वाले साहित्य उत्सव टाइमलेस अयोध्या का शुभारंभ किया। यहां पर उनके साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी, संगीत अध्येता और आयोजक यतींद्र मिश्र भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने राज सदन में अशोक के वृक्ष को जल अर्पण कर टाइमलेस अयोध्या कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके स्वागत के लिए सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी पहुंचे हैं।

घिनौने काम का शर्मनाक खुलासा

हाथरस का अय्याश प्रोफेसर गिरफ्तार

छात्राओं के अश्लील वीडियो पोर्न साइट पर डाले

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बहुचर्चित प्रोफेसर अश्लील वीडियो-फोटो कांड में आरोपी रजनीश कुमार को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। प्रोफेसर रजनीश के पीसी बागला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था। जिसके बाद से आरोपी प्रोफेसर फरार चल रहा था। बता दें कि प्रोफेसर रजनीश की 50 से भी अधिक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते वीडियो सामने आई हैं।

आपको बता दें कि पिछले दिनों महिला आयोग के साथ-साथ उच्चाधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा गया था। छुपे हुए नाम से भेजे गए इस शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने खुद को पीड़ित छात्रा बताया था। पत्र में कहा गया था कि बागला कॉलेज का भूगोल विभाग का प्रोफेसर डॉ रजनीश पिछले 20 साल से छात्राओं का लगातार यौन शोषण कर रहा है और उनकी अश्लील वीडियो और फोटो बना लेता है। पीड़ित छात्रा ने सबूत के तौर पर प्रोफेसर के अश्लील फोटो भी भेजे थे।

आरोपी प्रोफेसर छात्राओं को सरकारी नौकरी दिलाने और एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के बहाने उनके करीब जाता और फिर मौका पाकर उनकी अश्लील वीडियो बना लेता था। जिसके बाद उन्हीं वीडियो के नाम पर उन्हें धमकाकर उनका यौन शोषण करता था।

ऐसे चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड करता था प्रोफेसर

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रोफेसर रजनीश कुमार के पास से 1 मोबाइल, 1 लैपटॉप आदि सामान बरामद किया गया है। आरोपी प्रोफेसर ने अपने फोन और लैपटॉप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टाल किया था, जिसमें फ्रंट स्क्रीन ऑफ रहती थी लेकिन बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड होती रहती थी। बता दें कि इसी सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल करके प्रोफेसर ने 2019 में कॉलेज की एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ दुष्कर्म किया था। फिर डिग्री कॉलेज की कई छात्राओं को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था।

मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी जेल से हुआ रिहा

ईद से पहले परिवार में छाईं खुशियां

» नई दिल्ली, एजेंसी।

मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी ढाई साल से भी अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को बाहर आ गया। अब्बास को सात मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों पर अब्बास अंसारी को जमानत मिली थी। करीब 15 दिनों बाद कोर्ट का परवाना कासगंज जेल पहुंचा और अब्बास को रिहाई मिल सकी है। मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए ईद से पहले यह बड़ी खुशी है। रमजान के महीने में जुमे के दिन अब्बास के बाहर आने को भी उसके समर्थक खुदा की मेहरबानी मान रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ का दौरा करने से पहले प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अदालत की बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकेंगे। अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को जानकारी भी देंगे। अब्बास अंसारी को पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही 4 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर सबसे बड़ा मामला हेट स्पीच का था। इसके बाद 6 सितंबर 2024 को उनके ऊपर गैंगस्टर लग गया था।

अब्बास पहले चित्रकूट जेल में थे। यहां पत्नी निकहत के साथ अवैध रूप से मुलाकात करते पकड़े जाने पर कासगंज जेल भेजा गया था। निकहत को भी गिरफ्तार कर चित्रकूट जेल में रखा गया था। निकहत को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। अब्बास ने 2022 का विधानसभा चुनाव ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के चुनाव चिह्न पर जीता था।

विधायक अभय सिंह दोष मुक्त, दो जजों में बंट गया था फैसला

जानलेवा हमले में तीसरे न्यायाधीश ने दी बड़ी राहत

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

यूपी के बाहुबली विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। जानलेवा हमले में अभय सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। इससे पहले दो न्यायाधीशों की खंडपीठ का फैसला बंट गया था। एक न्यायाधीश ने अभय सिंह को दोषी बताया था और दूसरे ने दोष मुक्त कर दिया था। इसी के बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था। न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था। फैसलां बंट जाने से ही तीसरे जज न्यायमूर्ति राजन राय के पास मामला भेजा गया। राजन राय ने अभय सिंह को दोषमुक्त करारा दिया। इससे अभय सिंह के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला आया और राहत मिल गई है।

मामला अयोध्या के महाराजगंज थाने का है। अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराते हुए वर्ष 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर अभय सिंह व उनके साथियों ने जानलेवा हमला किया। बाद में मामले की सुनवायी अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। इसके खिलाफ विकास सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। यहां दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में मामले की सुनवाई चली थी। फैसलां बंट जाने के बाद तीसरे के पास आया था।

अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीते थे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बगावत कर दी और सपा की जगह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर दिया। इसी के बाद से उनकी गिनती सपा के बागी विधायकों में होती है। सपा की तरफ से उनकी सदस्यता को लेकर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसे में तकनीकी रूप से वह सपा के ही विधायक हैं लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम अवसरों पर भाजपा नेताओं के साथ ही दिखाई देते हैं।